



वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ का दूसरा शिखर सम्मेलन

प्रलिस के लयि:

वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समटि, [G20 शिखर सम्मेलन](#), G-77, ब्रांट लाइन, [लॉस एंड डेमेज फंड](#), [संयुक्त राषट्र](#), [IMF](#), [वशिव बैंक](#), [SAARC](#), [आसयान](#), [बमिस्टेक \(BIMSTEC\)](#)

मेन्स के लयि:

ग्लोबल साउथ का पुनरुत्थान, ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत के लयि चुनौतयिँ

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

भारत ने हाल ही में वरचुअल तरीके से आयोजति अपना दूसरा 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मलेन' (VOGSS) संपन्न कयि। यह शिखर सम्मेलन जनवरी 2023 में उदघाटन शिखर सम्मेलन के बाद संपन्न हुआ, जो राषट्रों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने तथा ग्लोबल साउथ में अपने नेतृत्व को सशक्त करने की भारत की प्रतबिद्धता को दर्शाता है।

दूसरे VOGSS की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- थीम: उदघाटन सत्र 'ट्रुगेदर, फॉर एवरीवनस ग्रोथ, वदि एवरीवनस ट्रस्ट' पर केंद्रति था, जबकि समापन सत्र में ग्लोबल साउथ: ट्रुगेदर फॉर वन फ्यूचर' पर ज़ोर दयिा गया।
- शिखर सम्मेलन का उददेश्य: भारत द्वारा आयोजति [G20 शिखर सम्मेलन के परणामों](#) का प्रसार करना तथा वकिसशील देशों के हतियों पर वशिष धयान देने के साथ G20 नरिणयों के प्रभावी कारयानवयन के लयि नरिंतर गति सुनशिचति करना।
- प्रमुख परणाम:
 - ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 'दकषणि': इस पहल का उदघाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने कयि, जसिका उददेश्य ज्ञानकोश तथा थकि टैंक के रूप में कार्य करके वकिसशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
 - वशिषगत चर्चाएँ: मंत्रसितरीय सत्रों में सतत वकिस लक्ष्य, ऊर्जा परविरतन, जलवायु वतित, डजिटिल परविरतन, महलाओं के नेतृत्व वाले वकिस, [आतंकवाद रोधी](#) तथा वैश्वकि संस्थान में सुधार सहति वशिषयों की एक वसितृत शृंखला पर चर्चा हुई।
 - इज़रायल-हमास संघर्ष के बीच संयम बरतने का आहवान: भारत ने इज़रायल-हमास संघर्ष से प्रभावति नागरकियों की दुर्दशा को लेकर गहरी चतिा व्यक्त की।
 - उन्होंने सभी संबंधति पक्षों को संयम बरतने, नरिदोष नागरकियों की सुरक्षा को प्राथमकिता देने तथा तनाव कम करने की दशिा में कार्य करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दयिा।
 - ग्लोबल साउथ के लयि 5 'Cs': भारत ने ग्लोबल साउथ के लयि 5 'Cs' का भी आहवान कयि, जसिमें परामर्श (Consultation), सहयोग (Cooperation), संचार (Communication), रचनात्मकता (Creativity) एवं क्षमता नरिमाण (Capacity Building) शामिल हैं।

ग्लोबल साउथ क्या है?

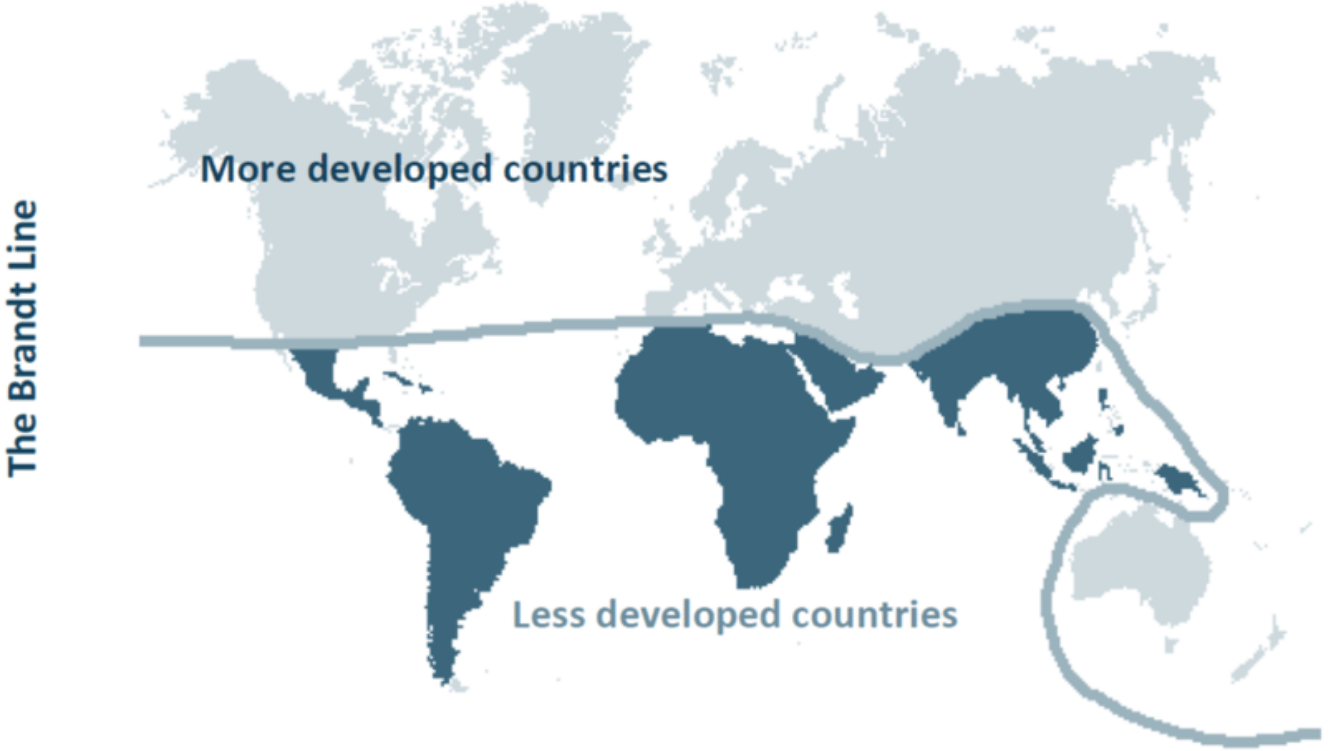
- परचिय:
 - ग्लोबल साउथ, जसि अमूमन पूरणत: भौगोलकि अवधारणा के रूप में गलत समझा जाता है, भू-राजनीतिक, ऐतिहासकि तथा वकिसात्मक कारकों पर आधारति वविधि देशों को संदर्भति करता है।
 - हालाँकि यह मात्र अवस्थति द्वारा परभाषति नहीं है, यह मोटे तौर पर वकिस संबंधी चुनौतयियों का सामना करने वाले देशों का प्रतनिधित्व करता है।
 - ग्लोबल साउथ में शामिल कई देश उत्तरी गोलार्ध में स्थति हैं, जैसे- भारत, चीन तथा अफ्रीका के अर्ध उत्तरी हसिसे में

स्थिति सभी देश ।

◦ जबकि, **ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड** जो दक्षिणी गोलार्ध में हैं, ग्लोबल साउथ में शामिल नहीं हैं ।

■ ऐतिहासिक संदर्भ:

- **ब्रांट लाइन (Brandt Line):** यह रेखा 1980 के दशक में पूर्व जर्मन चांसलर विली ब्रांट द्वारा प्रतिव्यक्तसकल घरेलू उत्पाद के आधार पर उत्तर-दक्षिण विभाजन के दृश्य चित्रण के रूप में प्रस्तावित की गई थी ।
 - यह रेखा वैश्विक आर्थिक विभाजन का प्रतीक है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को छोड़कर, अफ्रीका, मध्य पूर्व, भारत एवं चीन के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए महाद्वीपों में टेढ़ी-मेढ़ी होती जा रही है ।
- **G-77:** वर्ष 1964 में **77 देशों का समूह (G-77)** तब अस्तित्व में आया जब इन देशों ने जनिवा में **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)** के पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये ।
 - G-77 उस समय विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन बन गया ।



//

■ ग्लोबल साउथ का पुनरुत्थान:

- **आर्थिक गतिशीलता:**
 - **कोविड-19 के कारण आर्थिक असंतुलन:** महामारी ने मौजूदा आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया, सीमित स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचे, बाधित आपूर्ति शृंखलाओं और लॉकडाउन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर भारी नरिभरता के कारण इसने ग्लोबल साउथ देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला ।
 - **व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव:** महामारी के बाद तथा रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे हालिया भू-राजनीतिक संघर्षों के संदर्भ में वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्मूल्यांकन ने उत्पादन केंद्रों को फरि से स्थापित करने पर चर्चा शुरू की, जिससे कुछ ग्लोबल साउथ अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्र्गठन तथा अपनी भूमिकाओं को बढ़ाने का अवसर मिला ।
- **भू-राजनीतिक वास्तविकताएँ:**
 - ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ ने **G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोकप्रियता हासिल की**, जिससे शक्त की गतिशीलता में बदलाव आया और उनके दृष्टिकोण तथा हितों पर अधिक ध्यान देने के विचार को बढ़ावा मिला ।
- **पर्यावरण एवं जलवायु प्रभाव:**
 - **जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता:** ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन से असमान रूप से प्रभावित है, जिससे **जलवायु अनुकूलन**, लचीलापन-निर्माण और न्यायसंगत वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर चर्चा चल रही है ।
 - **नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास:** ग्लोबल साउथ के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और पर्यावरण संरक्षण पहल पर जोर दिये जाने से इसने वैश्विक समर्थन एवं ध्यान आकर्षित किया ।

कौन-सा साक्ष्य ग्लोबल साउथ के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है?

- मस्त्रि में COP27 के दौरान 'लॉस एंड डेमेज फंड' की स्थापना ने ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले अनुपातहीन भार को उजागर किया।
- जापान के G7 शिखर सम्मेलन ने अधिक समावेशी संवाद को बढ़ावा देते हुए भारत और ब्राज़ील जैसे देशों को शामिल करने का सराहनीय प्रयास किया।
- ब्रिक्स के 11 सदस्यों तक इसके वसितार से ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।
- क्यूबा में G-77 शिखर सम्मेलन महत्त्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिये कई विकासशील देशों को सफलतापूर्वक एक साथ लेकर आया।
- G20 में 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ का शामिल होना अफ्रीकी देशों के वैश्विक महत्त्व और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में उनके बहुमूल्य योगदान की बढ़ती मान्यता का प्रतीक है।

वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में भारत के लिये क्या चुनौतियाँ हैं?

- भिन्न हितों को संबोधित करना: ग्लोबल साउथ में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, आर्थिक संरचनाओं और भू-राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं वाले देश शामिल हैं। व्यापार, जलवायु परिवर्तन तथा सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर एकीकृत रुख प्रस्तुत करने के लिये इन मतभेदों में सामंजस्य बटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- शक्ति वषिमता पर काबू पाना: ग्लोबल साउथ में अल्प वकिसति देशों के साथ-साथ भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती हुई शक्तियाँ भी शामिल हैं。
 - इस समूह के भीतर शक्ति की गतिशीलता को संतुलित करना और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मज़बूत राष्ट्र छोटे, कम प्रभावशाली देशों पर हावी हो सकते हैं।
- वैश्विक शक्तियों के साथ बातचीत: वैश्विक शक्तियों के प्रभुत्व के बीच ग्लोबल साउथ के हितों का समर्थन करने के लिये कुशल रणनीतिक वार्ता की आवश्यकता होती है। भारत को अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी स्थापित शक्तियों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिये। सुनिश्चित करते हुए कि ग्लोबल साउथ के मत को वैश्विक नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में सुना और माना जाता है।
- संसाधन की कमी: भारत को ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका के साथ अपनी वकिसातमक प्रयासों को संतुलित करने की आवश्यकता है। ग्लोबल साउथ देशों के भीतर सीमति संसाधन और प्रतिस्पर्धी घरेलू प्राथमिकताएँ प्रायः भारत के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह

- क्षेत्रीय गठबंधनों को मज़बूत करना: क्षेत्रीय चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के लिये SAARC, आसियान, ब्रिक्स जैसी क्षेत्रीय समूहों के भीतर मज़बूत गठबंधन बनाना।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुगम बनाना: प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में एक-दूसरे की शक्तिका लाभ उठाते हुए, ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग एवं ज्ञान के साझाकरण को बढ़ावा देना।
- वैश्विक शासन में समानता का समर्थन: ग्लोबल साउथ के लिये नषिपक्ष प्रतिनिधित्व और अधिक नरिणय लेने की शक्ति सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक जैसी वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधारों पर ज़ोर देना।
- जलवायु परिवर्तन और स्थिरता को संबोधित करना: भारत टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने तथा ग्लोबल साउथ देशों की विकास संबंधी ज़रूरतों पर विचार करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने में उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न: नमिनलखिति में से कसि एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? (2020)

- अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की
- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूज़ीलैंड
- ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वयितनाम
- इंडोनेशिया, जापान, सगिापुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न: 'उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण उत्पीडित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है'। वसितार से समझाइये। (2019)

